

भारत पाक संघर्षों में चीन की नीति एक अध्ययन

सारांश

वर्तमान समय में चीन पाकिस्तान से बहत हो नजदोकियाँ बढा रहा है। नरेन्द्र मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद तो चीन भारत को विषय का शत्रू मानकर पाकिस्तान को हर प्रकार की सहायता करता नजर आ रहा है। जब की इतिहास बताता है कि इतिहास के गभ में भारत और चीन के सम्बन्ध काफी अच्छे थे। सांस्कृतिक सामाजिक एवं धार्मिक व्यवहार में भारत और चीन में काफी दोस्ताना सा माहौल रहा है। किन्तु १९६२ भारत चीन युद्ध के बाद चीन की नीति का प्रमुख आकर्षण यह रहा कि उसने भारत विरोधी वक्तव्य देने शुरु कर दिए। जिसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमणात्मक कार्यवाही करने हेतु निरंतर उत्सुक रहता है। चीन की कूटनीति में राजनितिक पर्यावरण को अपने पक्ष में करना और पाकिस्तान को बल देकर भारत को जर्जर बना देना है। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान ने श्रोनगर घाटि में अगस्त १९६५ से अब तक घूसपैठिये करना बन्द नहीं किया। इस संदभ में भारत पाक संघर्षों में चीन की नीति का अध्ययन करना इस शोधाआलेख का मुख्य हेतु है।

मुख्य शब्द : संघर्ष, घुसपैठिये, हवाईसेना, उपमहाद्वीप, पडोसी, आपरेशन जिब्राल्टर, ब्लेक आऊट, सतसेवा, अप्रत्यक्ष कूट नीति, सिद्धांत, प्रजातांत्रिक, नेशनल आवामी लीग, स्वयंनीति, इन्डरसन पेपर्स, पीपुल्स डेली, प्रावदा साम्रज्यवादो, आपसी मतेद।

परिचय

मशहूर सूफी संत मौलाना जलालउद्दीन रुमी का शेर है कि, तू बराबर वस्ल करदन आमदी न बराए फस्ल करदन आमदी' अर्थात तुझे एक को दूसरे से मिलाने के लिए जा गया है, अलग करने के लिए नहीं। इसे समूचे विश्व के लोक यदि समज ले तो जो एक दूसरे के खिलाफ यावह माहौल चला रहे है, वो कम होगा ऐसा मेरा मानना है।

१९६५ भारत पाकिस्तान युद्ध

१९६२ भारत-चीन युद्ध के बाद चीन की नीति का प्रमुख आकर्षण यह रहा कि उसने भारत विरोधी वक्तव्य देने शुरु कर दिए। जिसका परिणाम यह हुआ की पाकिस्तान भारत पर आक्रमणात्मक कार्यवाही करने हेत उत्सुक रहता है। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयुब खान की गहरी कूटनीति थी कि जहाँ एक और उन्होंने शांति स्थापना के पवित्र प्रयासों की चर्चा की वही इसकी आढ में कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए 'आपरेशन जिब्राल्टर' शुरु करने की योजना बना दी। जब पाकिस्तान ने अचानक ही छम्ब पर आक्रमण किया, तो भारतीय सेनाओ को पंजाब की सीमा पार करनी पडी और ६ सितम्बर १९६५ को लाहोर और सियालकोट की ओर बढना पडा। इस तरह से उपमहाद्वीप के दो निकटतम पडोसी राज्यों के बीच यौद्धिक स्थिती उत्पन्न हुई।^१ पहला युद्ध १९६२ में चीन ने भारत पर थोपा। १९६५ में भारत और पाकिस्तान दोनो ने एक दूसरे पर आक्रमण का आरोप लगाया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयुब खान ने कहा कि हम लोग भारत के साथ युद्धरत हो गये है। उनके विदेश मंत्री भूट्टो ने भी यह कहा कि भारतीय ने आक्रमण कर के यू एन चार्टर का उल्लघन कर दिया है। इस सशस्त्र संघर्ष में शोघ्र ही हवाई सेना भी शामिल हो गई, यह युद्ध पश्चिमी पाकिस्तान व भारत के पूरे पश्चिमी क्षेत्र पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर व गुजरात में लडा गया। वाय सेना ने भी आक्रमणकारी कार्यवाहीयों की जिससे दिल्ली, बम्बई व कलकत्ता में ब्लेक आऊट किया गया। पाकिस्तान जल सेना ने भी अरब सागर की और भारतीय तटीय स्थानों पर बम वर्षा की थी।

चीन ने इस युद्ध का पूरा लाभ उठाकर इस युद्ध में हस्तक्षेप किया। चीन के विदेश मंत्री ने अचानक ही पाकिस्तानी अधिकारियों से पाकिस्तान जाकर भट तथा विदेशी मंत्री भूट्टो से गोपनीय चर्चाये को थी। इसके बाद चीन ने भारत क खिलाफ पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से सहायता देने का शिलशिला जारी किया।^३ चीन ने भारत को युद्ध के लिए दोषी बताया और कहा की भारतीयों ने

के. एच. वासनिक

सहयोगी प्राध्यापक,
पदव्युत्तर राजनीति शास्त्र विभाग,
शासकीय विर्द ज्ञान विज्ञान
संस्था, अमरावती,
महाराष्ट्र

युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया। चीन ने यह भी कहा की वो कश्मीरी जनता के न्यायिक संघर्ष में उनके साथ है व भारत के खिलाफ है। चीन ने पाकिस्तान की ओर से भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने युद्ध विराम रेखा पार करके पाकिस्तान पर आक्रमण किया है।⁸ चीन द्वारा दिये गये बयान एवं की गयी कार्यवाहियों के कारण भारतीय सरकार को यह स्पष्ट कर दिया था कि चीन न केवल भारत के खिलाफ है बल्कि वह इस युद्ध में पाकिस्तान सैन्य बलों और शासकों को निर्देश देकर सहयोग कर रहा है। इसके विपरीत सोवियत सरकार ने दोनों पक्षों की अपनी सेनाये युद्ध विराम रेखा तक वापस लाने को कहा और दोनों के बीच सतसेवा (Good Officers) प्रदान करने का आमंत्रण भी दिया। ८ सितम्बर १९६५ को चीन ने पाकिस्तान का हौसला बढ़ाते हुए भारत को एक पत्र भजकर इस बात का विरोध दर्ज कराया कि भारतीय सेना पूर्वी और पश्चिमी विभागों में चीन की सीमाओं में भी घूस रही है। चीन ने यह भी कहा कि भारत सरकार को आक्रमणात्मक सेनाओं को वापस कर लेना चाहिए नहीं तो चीन को भी भारत चीन सीमा पर सैन्य कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। चीनी सरकार के प्रतिनिधी मण्डल के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने १९६२ से लेकर अब तक तिब्बत की भूमि पर लगभग ३०० सौ बार थल और वायु सेना द्वारा सीमा का उल्लंघन किया है।⁹ इससे यह सिद्ध होता है कि, चीन भारत को निरंतर बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

१९७१ भारत-पाकिस्तान संघर्ष

१९६५ का भारत पाकिस्तान युद्ध जो सितम्बर माह में हुआ वह दो वजह से महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत निश्चय ही इस युद्ध में पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा था। जिससे कि एक महत्वपूर्ण लाभ यह प्राप्त हो रहा था कि १९६२ में हुए भारत चीन युद्ध में भारतीय पराजय से भारत की प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा था। वो इस विजय से यकिनन भारत कि खोई हुई प्रतिष्ठा को बनाने वाला था। दूसरी ओर यह भी देखने को मिला कि १९६५ में पाकिस्तान की पराजय से चीन काफी तिलमिला गया था। भारत की उठती हुई सैन्य व कूटनीति प्रतिष्ठा को बर्दास्त नहीं कर पा रहा था। इसी कारण चीन अब यह सोचने के लिए मजबूर हो गया था कि जब तक वह अपनी ताकत को अन्य कूटनीतिक तथा सैनिक तरीको से बहुत ज्यादा ताकतवार नहीं कर लेता तब तक वह फिर कभी विषय में भारत पर आक्रमण करके उसे दोबारा पराजित नहीं कर पायेगा और नाही उसकी प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकेगा। इसलिए चीन के कूटनीतिज्ञों ने कई नई तरह कि सोच का बहुत विश्लेषण किया और उन्होंने अप्रत्यक्ष कूटनीति (Indirect Strategy) तैयार की जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदला और साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर उन्मुख होने वाली नीति बनाई।¹⁰ इस सन्दर्भ में इरान के शाह के बढ़ते हुए महत्व को भी ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी नीति को बनाने का अथक प्रयास किया। यही कारण था कि चीन ने एशिया में अपनी एकमात्र फतववादी छवि को बनाये

रखने के लिए पाकिस्तान को एक मोहरा बनाने की नियत से तथा अमेरिका से बैर कम करने का उद्देश्य लेकर इरान, पाक एवं चीन की एक धुरी बनाई जिसकी अमेरिका का बाहरी रूप से समर्थन प्राप्त था। चीन के द्वारा बनाई गई ये राजनीतिक धुरी भारत की सुरक्षा के लिए यकिनन एक गहरा खतरा था। जिससे कि भारत के पश्चिमी सीमान्त से लेकर उत्तर तथा साथ ही साथ दक्षिणी क्षेत्रों को भी दुष्प्रभावित कर रहा था।¹¹ यद्यपि चीन कट्टर साम्यवादी राष्ट्र है। जहाँ मार्क्स व माओ के सिद्धान्तों को मजबूती से देखा जाता है और बहुत मजबूती के साथ ही मौखिक दावे भी किये जाते हैं, कि जहाँ कहीं भी स्वतंत्रता आन्दोलन होंगे वे उनका समर्थन करेंगे और वही दूसरी ओर दक्षिण एशिया में भारत को कमजोर करने के लिए भारत पाकिस्तान संघर्ष को उकसाता अथवा चल रहे भारत पाक संघर्ष में पाकिस्तान को जो कि अमेरिका प्रभाव से मुक्त है को भारत के खिलाफ सहायता देना, चीन की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। चीन के द्वारा इस प्रकार पाक का समर्थन करके तथा अमेरिका साम्राज्यवादी हितों की रक्षा करके, अपनी प्रसारवादी नीतियों के द्वारा भारत जैसे समाजवादी प्रजातांत्रिक राष्ट्र के खिलाफ हर तरह से शडयन्त्र रचने की नीति अब जगजाहिर हो चुकी है। इस तरह से जहाँ एक ओर चीन अपनी मौलिक विचारधारा (साम्राज्यवाद का विरोध) से दूर हो गया है वही दूसरी ओर प्रजातांत्रिक राज्य भारत के खिलाफ पाक को उकसाने की तथा भारत पाकिस्तान के मध्य पिंग पिंग की नीति का प्रयोग किया था।¹² पाक शासक चीनी उदारता की नीति से प्रोत्साहित हुए और उन्होंने भारत के विरुद्ध अपनी नीतियों को और तीव्र कर दिया। साथ ही मजे की बात यह की, पूर्वी पाक लोगों के दिमाग में पश्चिमी पाक के प्रति दुर्भावना पनपने लगी। यही कारण था कि १९७० में हुए पाक के राष्ट्रीय चुनाव में बांग्लादेश के नेता शेख मुजिबुर रहमान ने नेशनल आवामी लीग ने बहुमत प्राप्त कर लिया जो इस बात को स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान में निश्चित रूप से उन लोगों को स्वीकार किया जा रहा था जो वाकई प्रजातांत्रिक और प्रगतिशील विचार है। इससे जहाँ एक ओर पाक के सामंतवादी नेताओं को धक्का लगा, वही दूसरी ओर चीन और अमेरिका दानों के लिए भी खतरे कि घंटों साबित हुई। अपने आपको दूध का धुला प्रजातांत्रिक नेता कहलाने वाले जुल्फिकार अली भट्टो ने हर वो अप्रजातांत्रिक कदम उठाया जिससे कि जनता के द्वारा दिये गये बहुमत को नष्ट किया जा सके। प्रजातन्त्र का पोषक कहलाने वाल राष्ट्र अमेरिका ने भी भट्टो के इन कदमों के प्रति कोई तीखा आलोचनात्मक स्वर नहीं उठाया एवं साम्यवाद का ढोंग करने वाले चीन ने पूर्वी पाक की निरीह जनता के स्वतन्त्रता आंदोलन के प्रति गैर संवेदनशील रुख अपनाया। इस सबके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण दिख रहा था वह यह कि अमेरिका तथा चीन दोनों ही यह चाहते थे कि भट्टो या हया खान तथा अयुब खान जैसे विचार वाले नेताओं का वर्चस्व पाक में बना रहे ताकि उनके छिपे हुए मनसुबे पुरे हो जाये और भारत को दक्षिण एशिया में सशस्त्र होने से रोका जा सके। इसलिए

पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान ने किये जाने वाले बेहद घृणात्मक कार्यों को जैसे जाति वध करना, बौद्धिक प्रखरता को नष्ट करना साम्रज्यवादी नीति अपनाना, दादागिरी दिखाना, स्त्रियों के साथ दुराचार करना, बच्चों और बूढ़ों का कत्लेआम करना, विश्व विद्यालय के प्राध्यापकों तथा छात्रों का नरसंहार करना आदि सर्वनाश कार्यों का चीन तथा अमेरिका ने कभी भी खुलकर विरोध नहीं किया। बल्कि इस क्षेत्र से ध्यान हटाने के लिए दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में वियतनाम, लाओस एवं कम्बूचिया जैसी समस्याये पैदा कर के तथा मध्य पूर्व में अरब इजराईल सघषो को हवा देकर यहाँ से ध्यान हटाने की कोशिश की गई। चीन द्वारा पाकिस्तान को इस समय भारी सैनिक सहायता प्रदान की गई। उदाहरण के लिए हवाई जहाज दिये गये तथा अन्य भारी सैन्य सहायता देकर पूर्वी पाकिस्तान में इस जन आन्दोलन को जो कि स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन कहा जा सकता है को कुचलने में चीन ने खुलकर मदद दी।¹⁵ यह नीति वास्तव में चीन के द्वारा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपनाई जानेवाली स्वयं की नीति का खुलकर उल्लंघन था। इन सबके पीछे कोई उद्देश्य दिखाई देता है तो वह यह कि चीन यही चाहता था कि पाकिस्तान का विभाजन ना होने पाये और वो कमजोर ना पड़ने पाये ताकि भारत को मजबूती के अवसर प्राप्त ना हो पाये। पूर्वी पाकिस्तान में किये जाने वाले अत्याचारों से परेशान होकर पूर्वी पाकिस्तानी जनता का एक बड़ा भाग लगभग एक करोड़ बंगाली मुसलमान भारत में घुस आये, जिनको रहने खाने का प्रबन्ध करने में भारतीय सरकार को लगभग २० मिलियन रुपया प्रतिदिन खर्च करना पड़ता था।¹⁶ भारत सरकार को यह बताना पड़ा की पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों पर ३०० करोड़ रुपये खर्च करना पड़ा। इस बात पर भारत की अपील थी कि, भारत पर भारी आर्थिक दबाव पड़ रहा है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी की उपरोक्त अपील पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन उदासीन बने रहे। चीन ने तो इसको बिल्कुल अनसुना कर दिया, इसका परिणाम यह हुआ की, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत से उपर आक्रमण की स्थिति बना दी। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहया खान इस बीच परिस्थितियों का आकलन कर चुके थे। इधर चीन से उन्हें सहयोग मिलने का पूरा एतबार था और अमेरिका की चुप्पी उन्हें इस बात का संकेत दे रही थी कि भारत पर इस समय आक्रमण करना पाकिस्तान के पुरे हित में है। परिणाम स्वरूप पाक ने भारत को धमकाते हुए आक्रमण की धमकी देदी और उन्होने अपनी धमकी को ३ दिसम्बर १९७१ को वास्तविकता में भी बदल दिया। इस तरह भारत पाकिस्तान के मध्य १४ दिन का युद्ध चला। इरान, पाक एवं चीन की धुरी को मजबूती प्रदान करते हुए अमेरिका ने अपना सातवां बेड़ा जो कि इन्टरप्राइज के नाम से जाना जाता था। और न्युकलीअर पावर से भी सम्पन्न था, को भारत के खिलाफ बंगाल की खाड़ी में भजने का निर्णय ले लिया था। दौरान चीन की सरकार ने भारत पर दबाव बनाने के लिए एवं पाकिस्तान को सहायता देने के लिए

एक अल्टीमेटम अत्यन्त कठोर भाषा में लिखा था। इस समय की परिस्थितियों का आकलन करते हुए इन्डरसन पेपर्स १५ फरवरी १९७२ को प्रकाशित किया था। इस पेपर में कहा गया कि अमेरिका की सेनाये इस समय एक आणविक युद्ध छेड़ सकती थी।¹⁷ परन्तु सोवियत संघ द्वारा अपना नेवल फ्लीट भारत के पक्ष में भजने से उन सम्भावनाओं को समाप्त कर दिया गया। जहाँ एक ओर अमेरिका के नीति कि दुनिया भर में आलोचना हो रही थी वही अन्य संदभ में चीन के कम्युनिस्ट विचार अमेरिका की साम्राज्य वादी नीतियों का गुणगान कर रहे थे। चीन ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध उकसाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया। इस सन्दभ में यह तथ्य समझना अनिवार्य है कि नवम्बर १९७१ में जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहया खान का दूत चीन से लौट आया तो याहया खान ने यह घोषण कर डाली कि अगर भारत व पाकिस्तान के मध्य कोई संघर्ष होता है तो चीन उसमें खुलकर पाक के पक्ष में हस्तक्षेप करेगा।¹⁸ लगभग इसी समय जुल्फिकार अली भट्टो ने जो कि उस समय पाक के विदेश मंत्री थे ने लाहौर में यह कहा कि, यदि भारत पाक में युद्ध हुआ तो पाक के कुछ परम मित्र उसके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर भारत के खिलाफ खड हो जायेगे और इसके लिए उन्हें कोई औपचारिक सन्धि करने की भी जरूरत नहीं होगी।¹⁹ नतीजन चीन ने पाकिस्तान को इस युद्ध में हर प्रकार से सहायता करके भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया। साथ ही साम्यवादी चीन ने १९७१ के भारत पाक युद्ध के पहले चरण में कई बार में घोषणाये व समाचार प्रकाशित किया की भारतीय उपमहाद्विप में यौद्धिक प्रवृत्तियों को बढ़ा रहा है। चीन के नेताओं में प्रमुख चाऊ एन लाई ने लन्दन से प्रकाशित होने वाले टाइम्स पत्र को अपना साक्षात्कार देत हुए कहा कि उनका राष्ट्र उपमहाद्विप में युद्ध की स्थिति पर पाक को पूर्ण रूप से समर्थन देगा तथा उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी पाक की समस्या लार्ड माऊंटबेटन की देन है। उनका यह मानना है कि पूर्वी बंगाल तथा तिब्बत की समस्याये एक जैसी है उन्होंने भारत एवम सोवियत मैत्री सन्धि को इस उपमहाद्विप की शांति के लिए खतरनाक बताया। चीन की इस नीति से यह सिद्ध होता है कि वो भारत को राजनैतिक और नैतिक दृष्टिकोण से कमजोर करना चाहता है ताकि एशिया में चीन के समान राजनैतिक आर्थिक और सैनिक दृष्टिकोण से सशक्त राष्ट्र का अभ्युदय ही ना हो, विदेशी समाचार पत्रों द्वारा यह भी प्रकाशित किया गया कि चीन ने पाकिस्तान फौजों को तिब्बत की भूमि से मशीनगन व मोटारें भजे है।²⁰ चीन के समाचार पत्रों में भारतवर्ष को भारत विस्तारवादी और अत्यन्त कलंकित राष्ट्र बताया गया, जब ७ दिसम्बर १९७१ को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की तो चीन ने इसे प्रसारवादी और हस्तक्षेप युक्त दृष्टिकोण बताया। चीन ने सुरक्षा परिषद (UNO) में भी भारत के खिलाफ अत्यन्त कठोर कदम उठाया और चीन के समाचार पत्र पीपुल्स डेली में १० दिसम्बर १९७१ को यह लिखा गया कि भारत तुरन्त रण विराम कर दे अथवा एक बार फिर से शर्मनाक पराजय का सामाना करने के लिए तयार रहे।²¹ भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दिये जाने पर खिस्सीयाये हुए चीन के नेताओं ने कहा कि ३० के दशक में जिस उत्तर पूर्वी चाइना

पर जपान ने अधिकार किया था और जिस तरह उसे सिर्फ नाजीवादी जर्मनी और फासेवादी इटली ने मान्यता दी थी। इस तरह भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी है। चीन द्वारा की गई इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि चीन को जब भी कोई मौका मिला तो वह भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाते से नहीं चुका। हालांकि यह बात गौर करने लायक है कि विश्व में वह भारत की छवि को खराब नहीं कर सका। दिसम्बर १९७१ के युद्ध की १६ दिसम्बर की रात्रि में चीन के अधिकारियों ने भारत पर दबाव बनाने के लिए यह घोषणा की कि भारतीय सेनाओं ने सिक्किम में उसके लगने वाली सीमाओं का भी अतिक्रमण किया व चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत पाक युद्ध की समाप्ति के बाद भी भारत पर अपनी तीखी आलोचनाएँ जारी रखी। साथ ही सावियत संघ पर भी भारत समर्थक होने का आरोप लगाया। चीन के इस वक्तव्य पर भारत के बजाय सावियत संघ ने अपने समाचार पत्र प्रावदा में १६ दिसम्बर १९७१ को चीन को जबाब देते हुए कहा कि भारतीय उपमहाद्विप में जो घटना घटी है उससे चीन का मुखौटा खुल गया है। अब पूरा विश्व यह देख सकता है कि चीन ने किस तरह स्वातंत्रता का अपहरण करने वाले राष्ट्र की मदद की है। उसमें लिखा गया कि पाकिस्तान तो सीटो और सेन्टो जैसे साम्रज्यवादी सैनिक संगठनों के सदस्य राष्ट्र है। चीन की यह भूमिका कारगिल युद्ध में २६/११ की घटना में और हाल ही में १६ दिसम्बर २०१४ को जो पाक में सैनिक स्कूल हादसा हुआ उसमें १५० बच्चे मारे गये इसमें भी चीन भारत के तरफ संदेह के निगाओं से देखता है और तुरन्त चीन ने प्रतिक्रिया दिया कि चीन पाकिस्तान को सहायता देने में अग्रसर रहेगा। यहाँ भले हो चीन कारगिल संघर्ष में भारत के खिलाफ रहा किन्तु १६७१ जैसी पाक समर्थित रहा वैसे चीन ने कारगिल युद्ध में अपने देश समाचार पत्रों में एवं विश्वस्तर पर भारत की कटू आलोचना नहीं की, यह एक उत्साहवर्धक स्थिति मानी जायेगी।^{१६} क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के कूटनीतिक सिद्धान्त में यह स्पष्ट किया गया है कि ना तो कोई स्थायि मित्र है और ना कोई स्थाई शत्रु राष्ट्रों के सम्बन्ध राष्ट्रीय हित के अनुसार सुधरते व बिगड़ते हैं। अब चीन भारत के साथ व्यापारिक सम्बन्धों की ओर उन्मुख हो रहा है। वर्तमान में भारतीय हितों के लिये चीन का यह बदलाव अति महत्वपूर्ण होगा। भविष्य में भारत चीन सम्बन्धों के कटूता के स्थान पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध एशियाई क्षेत्र की शांति व सुरक्षा के लिये बेहद आवश्यक है। यहाँ यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान समय में भारत की राजनैतिक, आर्थिक व वैज्ञानिक स्थिति अब पहले के तुलना में जादा मजबूत है। वैसेही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व में भारत की तस्वीर सुधारने में लगे हैं। इसका परिणाम आने वाले दिनों में सकारात्मक ही होगा।

निष्कर्ष

1. चीन भारत का विरोधी रहा है।
2. भारत पाक संघर्ष में चीन निरंतर भारत विरोधी और पाक समर्थित रहा है।
3. पाकिस्तान की सैनिक सहायता देकर मध्यपूर्व में अपना वर्चस्व रखना और पाकिस्तान को लगभग एक

सैनिक अड्डे की तरह इस्तमाल करने की अमेरिका नीति रही।

4. भारत चीन सीमाय ही युद्ध रोकने या युद्ध का कारण बनती है।
5. बदलती हुई विश्व अर्थव्यवस्था में भारत व चीन को शांति पूर्वक प्रतियोगिता करते रहना चाहिए ताकि दोनों राष्ट्रों का आर्थिक विकास हो सकता है।
6. सीमा विवाद मुद्दे पर शांति वार्ताओं द्वारा हल दुढने की प्रक्रिया में तेजी की आवश्यकता है। चीन को अपने अदियल दृष्टिकोण में लचकशीलता का मिश्रण करना चाहिए।
7. वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत की स्थिति व शक्ति को देखते हुए, यदि अमेरिका भारत को चीन के प्रतिद्वन्दी की तरह खड करना चाह रहा है तो इस स्थिति में भारत को इसका मोहरा बनने से सावधान रहना चाहिए।
8. पाकिस्तान को अपना वजूद बनाये रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का साथ ही सार्थक होगा, इसके लिए पाक को भारत विरोधी गतिविधियाँ को रोकना नितांत आवश्यक है।
9. कश्मीर का मसला केवल और केवल आपसी बैठकर हल करना चाहिए।
10. भारत पाक संघर्ष में चीन एवं अमेरिका की नीति सकारात्मक ही होनी चाहिए। इससे पाक में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है।

संदर्भ

1. डॉ. सोनकर सी. एल. — भारत में अस्पृश्यता एक ऐतिहासिक अध्ययन—किताब महल—एजेन्सीज इलाहाबाद—२०१० पृष्ठ क्र. ११।
2. Crisis in Kashmir - 1947-1966- A lastair lamb routledges Kegan Paul London- 1966 P. 144
3. Indian-China Relation - 1947-1971 (Friendship Goes with power part) Shri Ram Discovery Publisher New Delhi 1999 P. 108.
4. www.google.com
5. India-China Border dispute M.L. Sali (APH-Pub-corporation New Delhi-1998 P.N. 95
6. Tapar Das - China-Pakistan collusion and U.S. Policy Bombay Asia Publication-1972-Page 131.
7. Partiot New Delhi-29 Jan P.T. coll
8. Vinod Gupta Andrson papers New Delhi P.P.15-16
9. Statement cited by Nothern India patrika 15 feb. 1971
10. Bangladesh Birth of Nation Yatin dra Bhatnagar chief of New Bareace Hindustan P.N. 68
11. The Kargil war A sag of patriotism "R.N.Sharma Y.K. Sharma R.K. Sharma (Subhi pub. New Delhi 2003
12. Times : Sunday Edition London 5 Dec. 1971
13. Jayant Dhanpal - China and the third world (New Delhi Vikas pub house 1985 P. 115.
14. Swarn Singh-China-Sounth Asia-pub lancers book New Delhi year 2003 P. 329
15. The Hindu News paper-5 Jan-2015
16. चौधरी—अमिता—भारत—चीन—सम्बन्धों का अध्ययन राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली—२००६ .. ६३.